web: www.nyaysakshi.com | पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल | पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना
आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, गुरुवार, 30 जून 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-04, अंक- 272

पवन हंस हेलिकॉप्टर की अरब सागर में आपात लैंडिंग, 4 लोगों की मौत, 5 को बचाया गया

मुंबई (आरएनएस)। महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित अरब सागर में एक रिग के पास ओएनजीसी के पवन हंस हेलीकॉप्टर की आपातकालीन लैंडिंग में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई, जो देश की वाणिज्यिक राजधानी से लगभग 175 किलोमीटर दूर मुंबई हाई फील्ड्स से दूर है।

हेलिकॉप्टर नौ लोगों को ले जा रहा था जिसमें सात यात्री, कथित तौर पर ओएनजीसी के कर्मचारी, और दो पायलट थे और उन्हें बचाने के लिए ओएनजीसी, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और अपतटीय आपूर्ति जहाजों का एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया था।

अधिकारियों ने कहा कि दोपहर 2 बजे तक, सभी नौ लोगों को बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन चार, जो बचाव के बाद बेहोश हो गए थे उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

ओएनजीसी ने आज शाम एक ट्वीट में कहा, हेलीकॉप्टर पर सवार सभी 9 लोगों को बचा लिया गया। दुर्भाग्य से, उनमें से चार बेहोश होकर मुंबई बेस पर लाए गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। ओएनजीसी ने इस पर गहरा शोक व्यक्त किया।

मरने वालों के बारे में अधिक जानकारी, मृत्यु का कारण, उनकी पहचान आदि की प्रतीक्षा की जा रही है।

बचाव अभियान में ओएनजीसी के अपतटीय आपूर्ति पोत मालवीय-16 और ऑयल रिग सागर किरण की एक नाव शामिल थी, जबकि भारतीय तटरक्षक बल ने अपने हेलीकॉप्टरों को डूबे हुए हेलिकॉप्टर के पास राफ्ट छोडऩे के लिए तैनात किया था और भारतीय नौसेना ने एक एएलएच और एक सी किंग हेलिकॉप्टर भेजा था।

मुंबई और नई दिल्ली में ओएनजीसी के अधिकारियों के अनुसार, पानी पर आपातकालीन लैंडिंग का कारण मौसम से संबंधित या तकनीकी मुद्दों से संबंधित हो सकता है जो अभी तुरंत स्पष्ट नहीं है।

आरोपियों से एनआईए करेगी पूछताछ, पूरे राज्य में इंटरनेट बैन

जयपुर (आरएनएस)। राजस्थान के उदयपुर में दर्जी की निर्मम हत्या के बाद सरकार ने सख्ती बरती है। कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पूरे उदयपुर में 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा राज्य भर में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया है और अगले एक महीने के लिए सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसी बीच आज कन्हैया लाल का पोस्टमार्ट किया जाएगा।

बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा का सोशल मीडिया पर उदयपुर में मंगलवार को कथित रूप से समर्थन करने के आरोप में एक दर्जी की हत्या कर दी गई थी। दोनों हमलावरों ने इस घटना को कैमरे में भी रिकॉर्ड किया और एक अन्य वीडियो पोस्ट में कहा कि उन्होंने इस्लाम के अपमान का बदला लिया। बाद में उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। राजस्थान सरकार ने उदयपुर हत्याकांड की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया है। टीम में एडीजी एसओजी अशोक राठौर, एटीएस आईजी प्रफुल्ल कुमार और एक एसपी और एक एडिशनल एसपी शामिल हैं। एसआईटी टीम उदयपुर पहुंच गई है। इस हत्याकांड की जांच एनआईए भी करेगी। एनआईए की टीम भी आज उदयपुर पहुंचेगी।

वहीं गृह मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक से पहले सीएम गहलोत ने मीडिया से बातचीत की। जिसमें उन्होंने उदयपुर हत्याकांड को लेकर कहा कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। हम इस हत्याकांड की साजिश और इसके जुड़े लिंक को गंभीरता से जांच करवाएंगे।

महत्वपूर्ण एवं खास

उपराष्ट्रपति चुनाव का भी बजा बिगुल, 6 अगस्त को होगा मतदान; चुनाव आयोग का ऐलान

नई दिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भी बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने बुधवार को उपराष्ट्रपति चुवाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 6 अगस्त 2022 को वोट डाले जाएंगे और उसी दिन परिणाम भी आ जाएंगे। मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 11 अगस्त को खत्म हो रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 5 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वहीं, नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 19 जुलाई 2022 होगी। इसके बाद 20 जुलाई को उम्मीदवारों की स्क्रूटनी की जाएगी। वहीं, उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 22 जुलाई होगी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए अगर मदतान की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए 6 अगस्त को वोट डाले जाएंगे। मतदान का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। मतदान के दिन ही वोटों की गिनती भी की जाएगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे। राष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य हिस्सा लेते हैं। इस चुनाव मनोनीत सांसद भी अपना वोट डाल सकते हैं। इस तरह से देखें तो इस चुनाव में राज्यसभा के चुने हुए 233 सदस्य और 12 मनोनीत सदस्यों के अलावा लोकसभा के 543 चुने हुए सदस्य और दो मनोनीत सदस्य वोट करते हैं। हालांकि, राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा नहीं होता है। उसमें दोनों सदन के सदस्य के साथ-साथ विधायक भी वोट करते हैं।

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल का कार्यकाल विस्तार, 91 साल के अधिवक्ता 2017 में हुए थे नियुक्त

नई दिल्ली (आरएनएस)। वरिष्ठ अधिवक्ता केके वेणुगोपाल भारत के महान्यायवादी के पद पर तीन महीने और बने रहने को लेकर सहमत हो गए हैं। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उनका मौजूदा कार्यकाल 30 जून को समाप्त होना था। सूत्रों के मुताबिक वेणुगोपाल व्यक्तिगत कारणों की वजह से इस संवैधानिक पद पर बने रहने के इच्छुक नहीं थे। लेकिन, केंद्र सरकार के अनुरोध के बाद वह तीन महीनों के लिए भारत के शीर्ष कानून अधिकारी के पद पर और बने रहने के लिए सहमत हो गए हैं। वेणुगोपाल (91) को भारत के राष्ट्रपति द्वारा जुलाई 2017 में देश के महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें इस पद पर दोबारा नियुक्त किया गया। उन्होंने मुकुल रोहतगी की जगह ली थी। उच्चतम न्यायालय के प्रख्यात अधिवक्ता वेणुगोपाल ने बड़ी संख्या में संवैधानिक और कॉर्पोरेट कानून के महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़े मामलों में अपनी सेवाएं दी हैं। वह 1979 और 1980 के बीच भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी रहे। उन्हें 2002 में पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है।

अनिल देशमुख और नवाब मलिक पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, फ्लोर टेस्ट में शामिल होने की मांगी इजाजत

नई दिल्ली (आरएनएस)। महाराष्ट्र में जारी सत्ता संघर्ष का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट के आदेश के खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट में है। वहीं इसी बीच जेल में बंद महाराष्ट्र के विधायक अनिक देशमुख और नवाब मलिक ने भी सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उनकी मांग है कि फ्लोर टेस्ट होने पर वे मतदान करना चाहते हैं। दरअसल, जेल में बंद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे नवाब मलिक और राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों नेताओं ने महाराष्ट्र विधानसभा में गुरुवार को होने वाले फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए अनुमति मांगी है। शीर्ष न्यायालय आज शाम उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा। इससे पहले नवाब मलिक और अनिल देशमुख ने राज्यसभा चुनाव के समय ऐसी ही अर्जी बॉम्बे है कोर्ट में लगाई थी लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवाब मलिक को मतदान की मंजूरी न देने वाले सत्र न्यायालय के फैसले को ही जारी रखा था। फिलहाल अब एक बार फिर इन दोनों ने मौके की नजाकत को देखते है सुप्रीम कोर्ट से इसकी मांग की है। उधर महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई में अब उद्धव सरकार के सामने बड़ी चुनौती आ गई है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गुरुवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया है। भाजपा की मांग पर राज्यपाल ने कहा कि 30 जुलाई यानी गुरुवार को महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होगा।

हाई स्पीड एक्सपैंडेबल एरियल टार्गेट - अभ्यास - का ओडिशा के तट पर सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया

नई दिल्ली (आरएनएस)। अभ्यास - हाई स्पीड एक्सपैंडेबल एरियल टार्गेट (एचईएटी) का 29 जून, 2022 को ओडिशा के तट पर स्थित चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (आईटीआर) से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। उड़ान परीक्षण के दौरान निरंतर स्तर तथा उच्च गतिशीलता सहित कम ऊंचाई पर विमान का निष्पादन प्रदर्शित किया गया। टार्गेट विमान को एक पूर्व-निर्धारित निम्न ऊंचाई वाले उड़ान पथ में एक ग्राउंड आधारित कंट्रोलर से उड़ाया गया जिसकी निगरानी राडार तथा इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम सहित आईटीआर द्वारा तैनात विभिन्न ट्रैकिंग सेंसरों द्वारा की गई। अभ्यास की डिजाइन एवं उसका विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा किया गया है। इस हवाई वाहन को ट्विन अंडर-स्लग बूस्टर का उपयोग करने के जरिये लॉन्च किया गया जो व्हीकल को आरंभिक गति प्रदान करते हैं। यह हाई सबसोनिक स्पीड पर एक लंबी इंड्यूरेंस फ्लाइट को बनाये रखने के लिए एक छोटे से गैस टरबाइन द्वारा संचालित है। टारगेट विमान बहुत ऊंची उड़ान के लिए स्वदेशी रेडियो अल्टीमीटर तथा ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन तथा टारगेट विमान के बीच इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन के लिए डाटा लिंक के साथ-साथ गाइडेंस और कंट्रोल के लिए फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर के साथ नैविगेशन के लिए माइक्रो-इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम आधारित इनर्शियल नैविगेशन स्स्टिम के साथ सुसज्जित है। इस व्हीकल को पूरी तरह स्वचालित उड़ान के लिए प्रोग्राम किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभ्यास के सफल उड़ान परीक्षण के लिए डीआरडीओ, सशस्त्र बलों तथा उद्योग को बधाई दी है और कहा कि इस सिस्टम का विकास सशस्त्र बलों के लिए एरियल टार्गेट की आवश्यकता को पूरा करेगा।

हर-हर महादेव के जयघोषों के बीच अमरनाथ यात्रा के लिए 3000 श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना, उपराज्यपाल ने दिखाई हरी झंडी

जम्मू (आरएनएस)। हर-हर महादेव के जयघोषों के बीच श्री अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज सुबह रवाना हो गया है। श्री अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे को जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्री निवास भवन जम्मू से झंडी दिखाकर रवाना किया। जानकारी के मुताबिक करीब तीन हजार से ज्यादा श्रद्धालु आज तडक़े कश्मीर घाटी के लिए रवाना हो गए। यह यात्रा कोरोना संक्रमण की वजह से दो साल हो रही है।

यात्रा पर आतंकी खतरे की आशंका के मद्देनजर अधिकारियों ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। सीआरपीएफ के बाइक स्न्वॉड कमांडो यात्रियों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। यात्रा से पहले लश्कर ने धमकी दी है। इस संबंध में एडीजीपी जम्मू जोन मुकेश सिंह ने आजतक-इंडिया टुडे को बताया कि मामला दर्ज किया गया है और कुछ गिरफ्तारियां भी की गई हैं।

जानकारी के मुताबिक यात्रियों को ले जाने वाले वाहनों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लगाए गए हैं। चप्प-चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जम्मू-कश्मीर प्रशासन को इस साल रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है।

अमरनाथ यात्रा की शुरुआत इस बार 30 जून यानी कल से हो रही है। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा 11 अगस्त यानी रक्षाबंधन तक रहेगी। श्रद्धालु कड़ी सुरक्षा के बीच यात्रा करेंगे।

बाबा अमरनाथ धाम की यात्रा दो प्रमुख रास्तों से की जाती है। इसका पहला रास्ता पहलगाम से बनता है और दूसरा सोनमर्ग बालटाल से। श्रद्धालुओं को यह रास्ता पैदल ही पार करना पड़ता है। पहलगाम से अमरनाथ की दूरी लगभग 28 किलोमीटर है। ये रास्ता थोड़ा आसान और सुविधाजनक है। जबकि बालटाल से अमरनाथ की दूरी तकरीबन 14 किलोमीटर है, लेकिन यह रास्ता पहले रूट की तुलना में कठिन है।

शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले ने उत्तर भारत के 20 शहरों से गुजरने के बाद पश्चिमी भारत में प्रवेश किया

नई दिल्ली (आरएनएस)। पहली शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले ने आज सुबह जयपुर पहुंचने के साथ ही पश्चिमी भारत में प्रवेश किया। अजमेर से गुजरने के बाद यह मशाल रिले अहमदाबाद में प्रवेश करेगी और फिर केवडिय़ा, वडोदरा, सूरत, दांडी, दमन, नागपुर, पुणे, मुंबई और पंजिम की यात्रा करेगी। इसके बाद यह मशाल रिले भारत के पूर्वी भाग, उत्तर-पूर्वी भारत में प्रवेश करेगी और दक्षिण भारत में समाप्त होगी।

उत्तर भारत के पहले चरण में, यह मशाल पिछले 10 दिनों में दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 20 शहरों से होकर गुजरी।

यह रिले आजादी का अमृत महोत्सव - भारत की आजादी के 75वें वर्ष - के उपलक्ष्य में कुल 75 शहरों से होकर गुजरेगी। शतरंज ओलंपियाड के लिए पहली बार मशाल रिले का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 19 जून को नई दिल्ली के आईजी स्टेडियम में किया था।

फिडे के अध्यक्ष अर्कडी ड्वोरकोविच ने इस मशाल को प्रधानमंत्री को सौंपा, जिन्होंने इसे भारतीय शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद को सौंप दिया। ऐतिहासिक शुभारंभ के बाद, यह मशाल राष्ट्रीय राजधानी में लाल किला, धर्मशाला में एचपीसीए, अमृतसर में अटारी सीमा, आगरा में ताजमहल और लखनऊ में विधानसभा सहित अन्य ऐतिहासिक स्थानों से होकर गुजरी। इस शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों में उपस्थित रहने वाले प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों में जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा, पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू आदि शामिल थे।

इस मशाल रिले के कार्यक्रम सिमुल शतरंज के साथ शुरू होते हैं, जिसमें ग्रैंडमास्टर और गणमान्य व्यक्ति स्थानीय एथलीटों के साथ शतरंज खेलते हैं। इन कार्यक्रमों के बाद, यह मशाल जीप के जरिए विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती है। इसके अलावा, इस मौके पर एक शहर से दूसरे शहर तक जाने वाली एक संवादात्मक बस यात्रा तथा एक सांस्कृतिक परेड समेत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। सांस्कृतिक परेड अलग – अलग क्षेत्रों में अलग – अलग प्रकार की होती है और उसमें शतरंज के युवा खिलाड़ी शामिल होते हैं।

इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के इतिहास में पहली बार, भारत न सिर्फ 44वें फिडे शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी कर रहा है, बल्कि एक मशाल रिले की शुरुआत करने वाला पहला देश भी है। फिडे द्वारा 1927 में शुरू हुए इस प्रतियोगिता के इतिहास में पहली बार मशाल रिले की शुरुआत की गई है। मेजबान देश होने के नाते, भारत 44वें फिडे शतरंज ओलंपियाड में अब तक के अपने सबसे बड़े दल के रूप में 20 खिलाडिय़ों को मैदान में उतारने के लिए तैयार है। भारत ओपन और महिला वर्ग में से प्रत्येक में दो टीमों को मैदान में उतारने का हकदार है।

यूपी में बुलडोजर ऐक्शन के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 13 जुलाई तक टली, जमीयत ने डाली है अर्जी

नई दिल्ली (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर ऐक्शन के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने 13 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने शीर्ष अदालत में अर्जी दाखिल की है कि यूपी में बिना जरूरी प्रक्रिया के किसी की भी संपत्ति अथवा निर्माण को ढहाया न जाए। इससे पहले अदालत में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कहा था कि जिनके भी निर्माणों को ढहाया गया है, वे अवैध थे और उसके लिए पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया है। गर्मियों की छुट्टियों में सुनवाई के लिए बैठी जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी परदीवाला की बेंच ने कहा कि जब इस मामले की सुनवाई अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही है तो फिर उसे जारी रहने दिया जाए।

कोर्ट ने कहा कि कल ही इस मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में हुई थी और कल भी से सुनवाई की तारीख है। इसके अलावा जावेद मोहम्मद की पत्नी परवीन फातिमा ने खुद ही अपने केस को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। इससे पहले यूपी सरकार ने शीर्ष अदालत में हलफनामा दाखिल कर कहा था कि जो भी कार्रवाई हुई है, उसमें प्रक्रिया का पालन किया गया है। इसके अलावा बुलडोजर की कार्रवाई दंगों में आरोपी होने के चलते किसी के खिलाफ नहीं हुई है बल्कि अवैध निर्माण बनाने को लेकर की गई है। यूपी सरकार की ओर से हलफनामा दायर कर यह बात कही गई है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एमएनआरई व आईआरईएनए के बीच रणनीतिक साझेदारी समझौते को मंजूरी दी

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) एवं अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (आईआरईएनए) के बीच हस्ताक्षरित एक रणनीतिक साझेदारी समझौते से अवगत कराया गया। जनवरी 2022 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

इस समझौते का उद्देश्य भारत में अक्षय ऊर्जा पर आधारित हरित ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वाकांक्षी परिवर्तन, नेतृत्व और ज्ञान को बढ़ावा देना है। यह समझौता भारत के ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव के प्रयासों में मदद करेगा और दुनिया को जलवायु परिवर्तन से निपटने में भी मदद करेगा।

रणनीतिक साझेदारी समझौते में परिकल्पित सहयोग के क्षेत्र 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से प्रचलित 500 गीगावॉट स्थापित बिजली क्षमता के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत का समर्थन करेंगे। इससे आत्मनिर्भर भारत को भी बढ़ावा मिलेगा।

इस समझौते की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग बढ़ावा देना शामिल है। भारत से अक्षय ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के बारे में ज्ञान साझा करने की सुविधा। दीर्घकालिक ऊर्जा योजना पर भारत के प्रयासों का समर्थन करना। भारत में नवाचार के माहौल को मजबूत करने के लिए सहयोग करना। ग्रीन हाइड्रोजन के विकास की संभावना और इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देकर किफायती डीकार्बोनाइजेशन की ओर बढऩा।

द्विपक्षीय बातचीत में नीली अर्थव्यवस्था व सागर आधारित नवीकरणीय ऊर्जा जैसे विषयों पर चर्चा हुई

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत के विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने लिस्बन, पुर्तगाल में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सागर सम्मेलन के अवसर पर अलग से नार्वे के जलवायु और पर्यावरण मंत्री एस्पेन बार्थ ईड से पारस्परिक हित के अनेक विषयों पर बातचीत की।

यह बैठक पिछले सप्ताह नई दिल्ली में भारत में नार्वे के राजदूत हैन्स जैकब फ्राइडेनलैंड तथा पृथ्वी विज्ञान सचिव डॉ. एम. रविचन्द्रन के बीच नीली अर्थव्यवस्था पर 5वीं भारत-नार्वे कार्यबल की बैठक के बाद हुई। कार्यबल की बैठक में नई परियोजनाएं तथा दोनों देशों के समुद्री उद्योगों को जोडऩे के लिए रोडमैप तैयार करने पर सहमति हुई थी। दोनों देश हरित समुद्र, सतत सागर प्रबंधन, गहरी समुद्री टेक्नोलॉजी तथा अपतटीय पवन विषय पर सहयोग के उपाए तलाशने पर सहमत हुए थे।

डॉ. जितेन्द्र सिंह और एस्पेन बार्थ ईड ने 5वें भारत-नार्वे कार्यबल बैठक में अब तक की हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने एकीकृत सागर प्रबंधन, समुद्री प्रदूषण, हरित नौवहन, सागर आधारित नवीकरणीय ऊर्जा जैसे विषयों पर बातचीत और प्रगति की समीक्षा की।

दोनों मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच जारी सहयोग की सराहना की और आशा व्यक्त की कि भविष्य में साझेदारी और मजबूत होगी।

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने पिछले महीने भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के अवसर पर अलग से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और नार्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर से कोपेनहेगन में हुई बातचीत का उल्लेख किया, जहां मोदी ने कहा था कि नार्वे के कौशल और भारत के कार्य क्षेत्र में स्वाभाविक पूरकता पर प्रकाश डाला था।

कोपेनहेगन बैठक पर प्रधानमंत्री मोदी को उद्धृत करते हुए डॉ. जितेन्द्र सिंह ने नीली अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, सौर तथा पवन परियोजनाएं, हरित नौवहन, मछलीपालन, जल प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, अंतरिक्ष सहयोग, दीर्घकालिक अवसंरचना निवेश, स्वास्थ्य तथा संस्कृति जैसे क्षेत्रों में प्रगाढ़ सहयोग की संभावनाओं को रेखांकित किया।